

भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था

यह एडिटोरियल 30/04/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Mom, baby and us: Who takes care of the children?" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में अवैतनिक देखभाल कार्य के बहुआयामी पहलुओं और एक अधिक मूल्यवान, समावेशी एवं न्यायपूर्ण देखभाल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

प्रलिमिस के लिये:

चाइल्ड केयर अवकाश नीति, देखभाल अर्थव्यवस्था/केयर इकोनॉमी, [वर्ष 1995 का 'बीजगि प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन'](#), मातृत्व लाभ अधिनियम, [महलियाँ श्रम बल भागीदारी दर](#), महलियाँ से संबंधित SDG।

मेन्स के लिये:

देखभाल अर्थव्यवस्था, भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक नियन्य में हमियाचल प्रदेश में एक सरकारी महलियाँ करमचारी को चाइल्ड केयर लीव (CCL) दिये जाने से इनकार को उसके [संवैधानिक अधिकारों](#) का उल्लंघन माना गया।

इस नियन्य ने मुख्य रूप से महलियाँ द्वारा किये जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य के प्रायः उपेक्षणीय कर दिये जाने मुद्दे की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया है। भारत में महलियाँ अपने कुल समय का 84% अवैतनिक देखभाल कार्य पर खर्च करती हैं। अदृश्य, अप्रतिदिय, तुच्छ समझे जाते और गैर-चहिनति श्रम का यह भारी बोझ देश की देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy) की रीढ़ है।

इस लेख में बाल देखभाल और उत्तरदायित्व के अधिक समतामूलक वितरण की आवश्यकता पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था के बहुआयामी पहलुओं पर विचार किया गया है।

भारत में कार्यशील महलियाँ से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

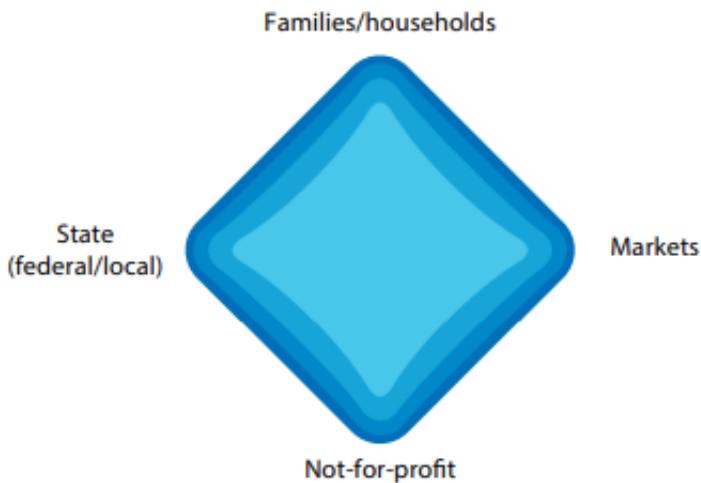
- **अनुच्छेद 14:** यह विधि के समक्ष [समता का अधिकार](#) को सुनिश्चित करता है, जहाँ कहा गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र में कसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह कार्यशील/कामकाजी महलियाँ पर भी लागू होता है।
- **अनुच्छेद 15:** यह धरम, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभिन्न का प्रतिष्ठित करता है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि महलियाँ को विभिन्न स्थानों पर प्रवेश, विभिन्न स्थानों के उपयोग आदि विषय में लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिये विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
- **अनुच्छेद 16:** यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की गारंटी देता है। यह महलियाँ को नियोजन से वंचित होने या उनके लिंग के कारण अलाभ का सामना करने से बचाता है।
- **अनुच्छेद 39: राज्य की नीति के नियंत्रक तत्व (DPSP)** के अंतर्गत शामिल इस अनुच्छेद में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की चर्चा की गई है, जहाँ कहा गया है कि राज्य अपनी की नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—
 - 39 (a): पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्रयोग साधन प्राप्त करने का अधिकार
 - 39 (d): पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन हो
 - 39 (e): पुरुष और स्त्री करमकार के सावधान्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विशेष होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गार से संलग्न नहीं हो पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
- **अनुच्छेद 42:** यह राज्य को कार्य की न्यायसंगत और मानवों की सुनिश्चिति करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करने का निर्देश देता है।
 - यह महलियाँ के लिये सुरक्षित कामकाजी माहौल और मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने के रूप में व्यक्त होता है।
- **केंद्र सरकार की CCL नीति:** यह महलियाँ करमचारियों को उनके संपूर्ण सेवा काल के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के अधिकारियों दो बच्चों की देखभाल के लिये मातृत्व अवकाश के अलावा 730 दिनों के संवैतनिक अवकाश की अनुमति देती है।

- लाभारथयों के रूप में महलियों के स्पष्ट उल्लेख को इस तथ्य की वैध मान्यता के रूप में देखा जा सकता है कियह मुख्य रूप से माताएँ होती हैं जो बच्चों के पालन-पोषण का भारी बोझ उठाती हैं, जो जन्म के बाद पहले छह माह (मातृत्व अवकाश के तहत मानी जाने वाली अवधि) से लेकर आगे की अवधितिक जारी रहती है।
- पुरुष CCL के लिये तभी पातर हैं यद्यपि एकल पति (single father) हैं।
- **महलियों के लिये सतत वकिस लक्षण:** **SDG 5** लैंगिक समता प्राप्त करने और महलियों एवं बालकियों को सशक्त करने पर लक्षण है
 - **5.1** सभी महलियों और बालकियों के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को हर जगह समाप्त करना।
 - **5.4** सार्वजनिक सेवाओं, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य को चहिनति करना एवं महत्वपूर्ण देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त तरीके के रूप में घर एवं परवार के भीतर साझा जिमिसेदारी को बढ़ावा देना।
 - **5.5** राजनीतिक, आरथिक और सार्वजनिक जीवन में नरिण्य लेने के सभी स्तरों पर महलियों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर को सुनिश्चित करना।
 - **5.c** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर सभी महलियों एवं बालकियों के सशक्तीकरण के लिये ठोस नीतियों एवं प्रवरतनीय विधान को अपनाना और उन्हें सुदृढ़ करना।

देखभाल अरथव्यवस्था (Care Economy):

- **परचिय:** देखभाल अरथव्यवस्था आरथिक गतिविधियों के उस क्षेत्र को संदर्भित करती है जिसमें देखभाल एवं सहायता सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है, वैशिष्ट्य रूप से वे सेवाएँ जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, वृद्धजनों की देखभाल और सामाजिक देखभाल के अन्य रूपों से संबंधित होती हैं।
 - इसमें मानव अस्तित्व, कल्याण और शरम शक्तिपुनरुत्पादन के लिये महत्वपूर्ण वैतनिक एवं अवैतनिक देखभाल कार्य शामिल हैं।
 - यह भौतिक, भावनात्मक और वकिस संबंधी आवश्यकताओं की पूरता में योगदान देता है लेकिन प्रायः इसे चहिनति नहीं किया जाता या इसे कम महत्वपूर्ण देखभाल अरथव्यवस्था' (hidden care economy) उत्पन्न होती है।
 - यह मुद्रीकृत अरथव्यवस्था (**Monetized Economy**) से अलग है, जो औपचारिक बाज़ार-आधारित प्रणाली है जहाँ धन का उपयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय किया जाता है।
 - इसमें वनिरिमाण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा (औपचारिक क्षेत्र) और खुदरा/रटिल जैसे उद्योग शामिल हैं।
 - मुद्रीकृत अरथव्यवस्था में कार्य का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उसके बाजार मूल्य से जुड़ा होता है।
- **इतहिस:** ऐतहिसिक रूप से, नारीवादी अरथशास्त्रियों ने अवैतनिक शरम (वैशिष्टकर घरों में महलियों द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान) को अपवर्जित करने के लिये 'कार्य' (work) की पारंपरिक परभाषा की आलोचना की है।
 - इसे दी गई चुनौती के परिणामस्वरूप **वर्ष 1995 का 'बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन'** का गठन हुआ, जिसमें देखभाल कार्य, घरेलू कार्य और स्वयंसेवा में महलियों की भूमिका को मान्यता एवं महत्व देने की विकालत की गई।
- **संबंधित शब्दावलियाँ:**
 - **वैतनिक देखभाल कार्य (Paid Care Work):** इसका तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू कार्य जैसे क्षेत्रों में देखभाल संबंधी ऐसी नौकरियों से है, जिनके लिये वेतन/पारशिरमकि प्रदान किया जाता है।
 - नर्स, घरेलू सहायकिया, वयक्तिगत देखभालकर्ता, शिक्षिका और बाल देखभाल सहायकिया जैसी देखभाल भूमिकाओं में महलियों अधिक संख्या में नायोजिति है।
 - **अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य (Unpaid Care and Domestic Work):** इसमें घरेलू सेवाएँ (खाना पकाना, सफाई करना), देखभाल कार्य (बच्चों, वृद्धों, बीमारों की सेवा करना) और सामुदायिक/स्वैच्छिक सेवाएँ शामिल हैं।
 - इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष देखभाल में आश्रितों की सेवा करना और अप्रत्यक्ष देखभाल में घरेलू कार्य करना शामिल होता है जहाँ बहु-कार्य या 'मलटीटास्किंग' से प्रायः ये सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं।
 - **केयर डायमड (Care Diamond):** यह देखभाल प्रावधान में चार मुख्य अभिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है- राज्य, बाज़ार, घर/परवार और समुदाय।

Care diamond



भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- **सीमति नीति कवरेज़:** देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित मौजूदा नीतियाँ (जैसे मातृत्व लाभ एवं शाश्वत देखभाल अवकाश) वशीष रूप से छोटे पैमाने के उदयमों और अनौपचारिक क्षेत्र परायः सीमति कवरेज एवं प्रयोज्यता रखती हैं।
 - **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961** के बल 10 से अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू है।
 - आर्थिक जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 98% भारतीय उदयम 10 से कम कामगारों के साथ सूक्ष्म (micro) उदयम श्रेणी के हैं।
 - पंजीकृत वनिरिमाण में भी 30% प्रतिष्ठानों में 10 से कम कामगार पाए जाते हैं।
 - इससे कई महलियों को कार्य और देखभाल की ज़मिमेदारियों के बीच संतुलन के नियमान्वयन में प्रयोग्यता समर्थन या सुरक्षा नहीं मिल पाती है।
- **सीमति कार्यबल भागीदारी:** देखभाल कार्य का असमान बोझ परायः महलियों की कार्यबल भागीदारी और करियर उन्नति के अवसरों में बाधा डालता है।
 - PLFS 2022-23 के अनुसार, भारत में **महलिया श्रम बल भागीदारी दर** वर्ष 2023 में 37% थी। पूरव की तुलना में इस प्रगति के बावजूद यह अभी भी वांछति स्तर से नीचे है।
 - कई महलियों को वैतनकि रोज़गार की तुलना में देखभाल को प्राथमिकता देने के लिये विविध कामयात्रा जाता है, जिसके परणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्रों और नियण्य लेने वाली भूमिकाओं में महलियों का प्रतनिधित्व कम हो जाता है।
- **देखभाल सेवाओं की अभिगम्यता का अभाव:** भारत के कई हिस्सों में वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाओं—जैसे किंबाल देखभाल सुवधा और वृद्ध देखभाल सहायता, तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है।
 - देखभाल सेवाओं की सीमति उपलब्धता तथा उच्च लागत के कारण पराविरों पर, वशीष रूप से नमिन आय वाले पराविरों पर, देखभाल का बोझ और अधिक बढ़ जाता है।
 - अनुमान है कि भिलियों द्वारा अवैतनकि देखभाल और घरेलू कार्य भारत की **GDP** के लगभग 15-17% के बराबर है।
- **सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक मानदंड़:** सामाजिक अपेक्षाएँ और सांस्कृतिक मानदंड परायः इस धारणा को मजबूत करते हैं कि देखभाल करना मुख्य रूप से महलियों की ज़मिमेदारी है।
 - यह कलंक पुरुषों को देखभाल संबंधी करतव्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकता है और घरों के भीतर देखभाल कार्य के असमान वर्तिरण के चक्र को निरित बनाए रखता है।

आगे की राह

- **3R (Recognize, Reduce, Redistribute) फ्रेमवर्कः**
 - वर्तमान में माताओं द्वारा वहन की जाने वाली व्यापक बाल देखभाल ज़मिमेदारियों को चहिनति करना (**Recognize**)।
 - **शाश्वत देखभाल के पुनर्वर्तिरण के माध्यम से माताओं पर भार करना (**Reduce**):**
 - घरों में पाति की अधिक भागीदारी से
 - घरों से बाहर वहनीय, गुणवत्तापूर्ण पड़ोसी शाश्वत देखभाल विकल्पों के माध्यम
 - बच्चों की देखभाल को एक सामाजिक उत्तरदायतिव के रूप में पुनर्वर्तिरति करना (**Redistribute**), न कि केवल माताओं पर एक व्यक्तिगत बोझ के रूप में बनाए रखना।
- **कौशल पहचान और माइक्रो-क्रेडेंशियलः** अवैतनकि देखभाल कार्य के माध्यम से प्राप्त कौशल की पहचान करने के लिये एक राष्ट्रीय ढाँचे का नियमान्वयन किया जाए।
 - इसमें माइक्रो-क्रेडेंशियल (micro-credentials) जारी करना शामिल हो सकता है जो बच्चों की देखभाल, वृद्धों की देखभाल या घरेलू प्रबंधन में दक्षताओं को मान्यता प्रदान करता है। ये प्रमाण-पत्र उन देखभालकर्ताओं की रोज़गार-योग्यता को बढ़ा सकते हैं जो वैतनकि

- कार्यबल में पुनः प्रवेश करते हैं।
- देखभालकर्ताओं द्वारा अपने कौशल को बेहतर बनाने और संभावित रूप से वैतनिक देखभाल भूमिकाओं में आगे बढ़ सकने में मदद करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करें।
- देखभाल अरथव्यवस्था में नविश बढ़ाना:** **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** का मानना है कि देखभाल सेवा क्षेत्र में नविश की वृद्धिविष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन नौकरियाँ सृजित कर सकने की क्षमता रखती है।
 - वर्तमान में देखभाल अरथव्यवस्था पर भारत का सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है, जो अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
 - सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक नविश से भारत में संभावित रूप से 11 मिलियन नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं, जिनमें से लगभग 70% महिलाओं को प्राप्त होंगी।
 - भारत जापान के 'वीमनोमक्रिस' (womenomics) सुधारों से भी प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार:** देखभालकर्ताओं को संसाधनों एवं सहायता सेवाओं से जोड़ने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के नियमण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए। ये प्लेटफॉर्म बाल देखभाल विकल्पों, वृद्धजन देखभाल सुविधाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं।
- सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP):** सस्ती एवं सुलभ देखभाल सेवाओं के लिये नवीन समाधान विकसित करने हेतु सरकार, नजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
 - इसमें उन कंपनियों के लिये कर छूट देना शामिल हो सकता है जो अपने कर्मचारियों के लिये बाल देखभाल सुविधाएँ प्रदान करती हैं या देखभाल क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक उद्यमों को सहायता प्रदान करती हैं।
 - देखभाल अरथव्यवस्था का समर्थन करने वाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायत्व (CSR) पहलों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें नमिन-आय समुदायों में बाल देखभाल केंद्रों को प्रायोजित करने वाली कंपनियाँ या देखभाल उत्तरदायत्व रखने वाले कर्मचारियों को लचीली कार्य व्यवस्था की पेशकश करने वाली कंपनियाँ शामिल हो सकती हैं।

अभ्यास प्रश्न:

लैंगिक समानता और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अवैतनिक देखभाल कार्य के प्रभाव पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में देखभाल अरथव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये।

प्रश्न : 'देखभाल अरथव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अरथव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अरथव्यवस्था को मुद्रीकृत अरथव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (250 शब्द)